सरकार के ध्यान में आई है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सीलमपुर कालोनी के झुग्गी निवासियों के पुनर्वास के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Functioning of BALCO

771. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Public sector undertaking Bharat Aluminium Company (BALCO) has been incurring losses worth lakhs of rupees every year due to agitation by the local people of the Sambhalpur;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what steps are being contemplated by Government to normalise the functioning of the BALCO?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF MINES IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) to (c) The work on Gandhamardan Bauxite Project of Bharat Aluminium Company Ltd. (BALCO) in Orissa has been slowed down considerably since December, 1985 due to the agitation by the local people apprehending damage to the forests, temples and ecology of the area as a result of bauxite mining. Due to the stoppage of work BALCO has been incurring unremunerative expenditure of about Rs. 3 lakhs per month by way of wages, etc. The matter is receiving attention of the Government at a high level in order to resolve the issue.

दिल्ली में झुग्गी वासियों को भूमि का आवंटन

772. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** . क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले उन लोगों को, जो कि तीन वर्षों से अधिक समय से लगातार वहां रह रहे हैं, मकान या प्लाट उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उन्हें मकान या प्लाट कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) झुग्गी झोंपड़ी निवासियों को मकानों/प्लाटों के आवंटन के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है परन्तु अनधिवासियों सहित समाज के निम्न स्तर/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को विकसित प्लाटों के प्रावधान हेतु एक योजना बनाई जा रही है। ज्यों ही यह योजना प्रवृत्त कर दी जाएगी, झुग्गी निवासी उस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

विधवाओं और गरीब व्यक्तियों को मकानों या प्लाटों का आवंटन

773. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में उन विधवाओं और गरीब व्यक्तियों को, जिनकी मासिक आय 750 रुपये से कम है, दिल्ली में 21 वर्ग मीटर के प्लाट पर निर्मित मकानों के आवंटित किए जाने की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को देश के सभी राज्यों में भी कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है,

यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भविष्य में इन व्यक्तियों की दयनीय स्थिति में तेजी से सुधार लाने के लिए योजना के कार्यान्वयन में कोई विसंगति पाई गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ग) ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है तथापि, 1987 को बेघर लोगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आश्रय वर्ष के रूप में मनाने के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण के मलिनबस्ती विभाग ने हुडको के सहयोग से मादीपुर में 29-1-87 को राष्ट्रीय स्थल व आश्रय प्रदर्शन परियोजना आरम्भ की थी। इस परियोजना में हुडको द्वारा तयार किए जा रहे मार्गदर्शन/डिजाइनों पर ग्रुप आवास संकल्पना में 21 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के प्लाट पर आसान शर्तों पर बने बनाये मकानों की व्यवस्था पर विचार किया गया है। 700/- रुपये प्रतिमाह या इससे कम आय वाली आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की विधवाओं और जो पहले पंजीकरण योजना, 1985 के अन्तर्गत रिहायशी फ्लैटों के आवंटन के लिए पंजीकृत थीं, को आवंटन के लगभग 250 बने-बनाये मकान निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Tribal Sub Plan and Special Component Plan

774. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI:
SHRI KALPNATH RAI:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether any schemes are under implementation under Tribal Sub-Plan and Special Component Plan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is the progress made and targets achieved during the last 2 years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) Yes, Sir. The Tribal sub-plan and the Special Component Plan are plans within the State Plan with particular focus and emphasis on the development of Scheduled Tribes and Scheduled Castes respectively. All relevant schemes for the development of these communities are taken up under various sectors of development such as agriculture, animal husbandary, minor irrigation, cooperation, social services, forestry, cottage and small industries, etc., under Tribal sub-plan and Special Component Plan.

(c) During 1985-86 and 1986-87 the number of Scheduled Tribe and Scheduled Caste families targetted to be economically assisted and achievement thereof were:—

(Number in Lakhs)

	ST families		SC families	
	Target	Achievement	Target	Achievement
1985-86	8.35	8.73	21.41	22.73
1986-87	8.35	7.93 (upto February, 1987)	19.32	18.32 (upto February, 1987)